

:: न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व विभाग जवाहरपुर म.प्र. ::

PBR/मिगरानी/धार/भू-रा/2017/6017

105

बाबु पिता भेरा जाति तेली आयु 70 वर्ष,
व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम हातोद, तहसील
सरदारपुर, जिला धार म.प्र. प्रदेश - प्रार्थी/निगरानी
कर्ता

विरुद्ध

पुनिया उर्फ पुनमचंद पिता भेराजी जाति तेली,
आयु 45 वर्ष, व्यवसाय नोकरी, निवासी
इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. प्रदेश - विपक्षी

:: निगरानी धारा 50 मू. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में निगरानीकर्ता तरफ से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक
अर्ज है कि ग्राम केसरपुरा निधानिया षटवारो हल्का नम्बर 42/84 तहसील
सरदारपुर में भूमि सर्वे क्रमांक 29 रकबा 1.442 हेक्टर, 30/2 रकबा
2.508 हेक्टर कुल नम्बर 22 कुल रकबा 2.393 हेक्टर लगान 11-00 रुपया
की भूमि के संबंध में इस प्रकरण के विपक्षी पुनिया ने धारा 178 मू. रा. स.
के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की, उरकार्यवाही में प्रार्थी यानि निगरानीकर्ता
को सूचना दिये बगैर मौजा षटवारो से जांच रिपोर्ट तलब करने बाबद आदेश
व बिना आदेश के एकाएक बिना विपक्षी को आवेदन-पत्र कानोटिस तामील
कराये एकाएक फर्द बंटवारा व बटॉकिन प्रस्तुत करेन बाबद आदेश नही होते
हुवे फर्द बंटवारा व नक्शा बटॉकिन प्रस्तुत कर दिया जिस संबंध में प्रोसीडिंग
दिनांक 17-10-2017 व प्रोसीडिंग दिनांक 7-11-2017 के आदेश से
व्यथित होकर निगरानीकर्ता कोतरफ से यह सिगरानी निम्न आधारों पर
सादर सद्भावनापूर्वक नकल के दिन मुजरा जाते अन्दरअवधि प्रस्तुत है ।

:: आ धा र - नि ग रा नी ::

[Handwritten signature]

दी. से. मु. का. 12-12-17

आज 12-12-17

12-12-17

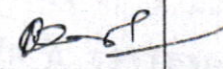
3-1-18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **PBR/जिग/धार/२२/२०१७/६०१७**

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमापकों आदि के हस्ताक्षर
13.12.2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द पर आवेदक की सहमति/असहमति हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

